"टिहरी बाँध हिमालय में बनने वाले दर्जनों बांधों में से एक है और हिमालय की स्थलाकृति,वहाँ का जन जीवन, परिस्थिति की और अर्थ व्यवस्था पर तथा सारे देश पर इन परियोजनाओं का दूरगामी प्रभाव क्या होगा? इस महाप्रश्न का दिल्ली और लखनऊ के उन राजकर्ताओं को उत्तर देना है, जो टिहरी जैसे बांध बनाकर अपने ही नागरिकों को जिन्दा रहने के अधिकार छीन रहे हैं।[25]"

अपील (टिहरी बाँध विरोधी संघर्ष समिति की ओर से सर्वश्री सुन्दरलाल बहुगुणा, वीरेन्द्र दत्त सकलानी और विद्या सागर नौटियाल ने केन्द्रीय सरकार से अपील की:

"हम आपका ध्यान टिहरी बाँध परियोजना से विस्थापित होने वाले 86000 लोगों तथा इसके ऊपर व नीचे गंगा घाटी में बसने वाले लाखों लोगों के जीवन के लिये खतरे की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।..... इस बाँध परियोजना का कार्य आरम्भ होने के समय से ही हम टिहरी गढ़वाल के लोग इसका विरोध करते रहे हैं। (हम सरकार, संसद और उच्च न्यायालय में भी अपनी आवाज पहुंचाते रहे जिससे समस्या की गंभीरता को समझे।"

"हमारी आशंकाओं को भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा सुनील कुमार राय की अध्यक्षता में नियुक्त कमेटी ने पुष्ट किया, कमेटी की राय में यह परियोजना पर्यावरण की दृष्टि से घातक है। इसके पश्चात वन और पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय हित में इस योजना को पूर्णतया समाप्त करने की सिफारिश की थी।"[26]

नर्मदा बचाओ आन्दोलन (Save Narmada)

सरदार सरोवर बांध आरम्भ से ही विवादास्पद रहा है। 1994 तक यह थमा नहीं था। इस परियोजना के विरोध में नर्मदा घाटी में चल रहा जन आन्दोलन विकास की सोच के तहत चल रहे आन्दोलन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। गत 8 वर्षों से नर्मदा घाटी के बूढे, जवान, स्त्री, बच्चे इस परियोजना के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के आन्दोलन कर्त्ता चीख-चीख कर कहते हैं कि चन्द लोगों की खुशहाली के लिये प्रकृति और संसाधनों का मनमाने ढंग से दोहन किया जा रहा है। विकास की प्रचलित अवधारणा के विरुद्ध, नर्मदा घाटी में व बाहर एक चुनौती के रूप में यह आन्दोलन किया जा रहा है।

नर्मदा पर बनने वाला यह बाँध आरम्भ से ही विवादों के घेरे में रहा है और जिस समय वर्ल्ड बैंक ने अपने ऋण सहायता 170 मिलयन डालर के वायदे को वापस ले लिया, वे लोग जो बाँध निर्माण का विरोध कर रहे थे, वे अपनी जीत पर बेहद खुश थे। विश्व बैंक परियोजना से हट जाने के बाद भी लोग आन्दोलन करते रहे कि 'डूबेंगे पर नहीं हटेंगे' संकल्प दोहराते रहे। आदिवासियों ने डूब का सामना किया। पुलिस हमले हुये। महिलाओं

25. सुन्दरलाल बहुगुणा, हिमालय बचाओ आन्दोलन, पृष्ठ 37.
26. सुन्दरलाल बहुगुणा, हिमालय बचाओ आन्दोलन, पृष्ठ 40.

Scanned with CamScanner

के साथ बलात्कार किया गया। गोलियाँ चलाई गयी। पुलिस फायरिंग में रेहमल वसावे मारे गये। (19 नवम्बर 1993) अंततः केन्द्र सरकार ने बाँध पर सम्पूर्ण पुनर्विचार करने की घोषणा की। इस कार्य हेतु एक दल गठित किया गया। 31 दिसम्बर 1993 को बाँध का निर्माण कार्य रोक दिया गया। इस समय मध्य प्रदेश सरकार ने इस परियोजना पर प्रश्न खड़े किये और नर्मदा घाटी की परियोजना में आमूलचूल परिवर्तन लाने की पेशकश की।

गुजरात सरकार नर्मदा घाटी के कार्य को रोकने से सहमति नहीं दिखा रहे थे। वे जनता को नर्मदा बांध निर्माण के लिये प्रोत्साहित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे, किन्तु 'नर्मदा बचाओ आन्दोलन' इसका डटकर विरोध कर रहा था। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के असंख्य व्यक्ति बांध बनाने की परियोजना से कहीं भी सहमत नहीं थे।

नर्मदा बचाओ आन्दोलन की नायक मेधा पाटकर थीं। वे नर्मदा बाँध निर्माण के विरोध में मुम्बई में आमरण अनशन पर बैठ गईं और यह माँग की कि केन्द्रीय सरकार बाँध निर्माण परियोजना पर पुनर्विचार करे। लगभग 2 सप्ताह तक आमरण अनशन पर बैठी रहीं। अन्ततः मेधा पाटकर को सफलता प्राप्त हुई। सरकार ने वार्ता के लिये न्योता दिया। इसके साथ ही परियोजना पर पुनर्विचार कराने की मंशा जाहिर की। किन्तु इसी समय अधिक मानसूनी वर्षा होने के कारण बाँध में पानी की ऊंचाई 61 मीटर तक पहुंच गयी। शूपेनेश्वर का मन्दिर लगभग डूब गया जो लगभग 1000 वर्षों में भी डूबा नहीं था। सब जगहों पर त्राहि-त्राहि मच गयी। लोग ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। व्यक्ति पलायन करने के लिये विवश हो गये। सामान पानी में डूब गये। बह गये। खेत जलमग्न हो गये। अनेक आश्वासनों के पश्चात भी केन्द्रीय सरकार ने बाँध पुनर्वालोकन की कमेटी घोषित नहीं की। अन्ततः नर्मदा बचाओ आन्दोलन ने जेल सर्मपण का निर्णय लिया।

मीडिया की भूमिका इस मुद्दे को उछालने में सराहनीय थी। अंततः परिणाम यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार ने कमेटी गठित करने का निर्णय लिया और तीन माह के अन्दर रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने का वचन दिया।[27]

यह सफलता मनोवैज्ञानिक अधिक और वास्तविक कम थी और न इसकी ही गारन्टी थी कि जो तथ्य उभर कर सामने आयेंगे उसे केन्द्र अथवा राज्य की सरकारें मानने के लिये विवश होंगी। इस प्रकार का समझौता हुआ था कि नर्मदा बाँध परियोजना का कार्य रोक दिया जायगा। राज्य सरकार को भी कोई आदेश देने की बात नहीं कही गयी। अन्ततः यह रिपोर्ट समय की गर्द के नीचे दब गई। नर्मदा बचाओ आन्दोलन भी ठन्डा पड़ता गया। आन्दोलनकारी हताश से दिखने लगे और धीरे-धीरे पीछे हटते दिखायी पड़ने लगे। इसी मध्य गुजरात हाई-कोर्ट में रिट दायर की गयी कि रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से पूर्व इसकी घोषणा न की जाय।[28] नर्मदा कन्ट्रोल अथारिटी (एन.सी.ए.) ने भी यह सुझाव दिया कि पर्यावरण

27. कल्पना शर्मा, सर्वे आफ द इनवायरामेन्ट, 1995, पृष्ठ 185:186.
28. कल्पना शर्मा, सर्वे आफ द इनवायरामेन्ट, 1994, पृष्ठ 153.

Scanned with CamScanner

संबंधी जो भी कदम उठाये गये हैं वे पर्याप्त नहीं है। केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भी यह कहा कि पर्यावरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इन आधारों पर बाँध निर्माण का कार्य रोक दिया गया। प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव ने कहा कि जब तक पर्यावरण संबंधी सारे मुद्दे तय नहीं हो जाते बाँध का काम आरम्भ नहीं किया जायगा। इसे नर्मदा बचाओ आन्दोलन ने अपनी सफलता माना।

इसी समय भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में असफलता का मुँह देखना पड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंह बने। कांग्रेस की सरकार बनी। मुख्य मंत्री का मत था कि मध्य प्रदेश को बांध से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा बल्कि अधिक से अधिक भूमि की क्षति होगी। इसके साथ ही लोगों की पुनर्वास की समस्या भी खड़ी होगी। इसलिये आवश्यक है कि बाँध की ऊंचाई कम की जाय जो 138.68 मीटर (455 फीट) है उसे कम करके 118.26 मीटर (388 फीट) किया जाय। मध्य प्रदेश की सरकार का यह कहना था कि बाँध का जल स्तर कम होने से 38,000 व्यक्तियों का पुनर्वास कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपेक्षाकृत 1,50,000 के 'नर्मदा बचाओ आन्दोलन' ने बांध निर्माण के विरुद्ध आन्दोलन किये पर व्यक्तियों को 1995 तक पुनर्वास के लिये विवश किया जा रहा था।

मेधा पाटकर 'नर्मदा बचाओ आन्दोलन' की नायक है। बाँध के संबंध में उनके मार्मिक विचार देखते ही बनते हैं ''हम चाहते हैं कि छोटे से पर अनूठे कदम से हमारे दलित-पीड़ित, शोषित, आदिवासी, किसान, मज़दूरों को आज तक फैलाए गए झूठे विकास को चुनौती देने का बल मिले, अपने जीवन को ही हथियार बनाकर संघर्ष में उतरने की वे तैयारी बताएं।''

''इस देश में जो भी सम्वेदना जिन्दा हो, उसी से नर्मदा घाटी बचाने का विवेक और गुजरात की जनता को भी झूठे सपनों से जगाने की प्रेरणा उभर कर आये। हमारे (आत्मसमर्पण) से हमारी छोटी सी जिन्दगी तो समाप्त होगी, लेकिन मानव व प्रकृति के निरन्तर एवं न्यायपूर्ण रिश्तों पर आधारित सही विकास को समझकर भी आज तक किसी न किसी कारण सक्रिय न हुए, दलीय राजनीति, संगठनों से जुड़े या अपने में ही खोए हुए हजारों लाखों लोग सक्रिय हो उठे, यही हमारी आशा है। नर्मदा की घाटी में चल रहे संघर्ष की अन्तिम दम तक विवेक के सिद्धान्तों के आधार पर जिन्दा रहने की, तार्किक परिणिति है हमारा कदम।[29]''

1985 से लगातार नर्मदा घाटी के लोग अपना मुद्दा पकड़े हुए हैं। विश्व बैंक जैसी महासत्ता को बाँध परियोजना से अपने को अलग करना पड़ा। यह नर्मदा आन्दोलन की बहुत बड़ी सफलता थी। अब मध्य प्रदेश राज्य ने अनेक प्रश्न खड़े किये हैं। केवल सरदार सरोवर ही नहीं देश में अब तक बनाए गए बांधों का मूल्यांकन अब नये जनवादी परिप्रेक्ष्य से और वैकल्पिक विकास की अवधारणा को दृष्टि में रखकर करने की आवश्यकता है। संसार के राजनीतिक जल की समस्या को लेकर चिन्तित हैं। चीन जैसे समाजवादी देश में

---

29. हम लड़ेंगे साथी, नारायण पेठ, पूणे, पृष्ठ 58-59.

Scanned with CamScanner

जल का गंभीर संकट है। भारत के प्रतिनिधि जब चीन भ्रमण से लौटे तो बताया कि वहाँ नहाने के पानी के लिये पैसे देने पड़ते हैं। इसीलिये कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा। अस्तु आवश्यकता है जल के प्रबन्धन करने की और वैकल्पिक संसाधन जुटाने की, जिससे जल का सदुपयोग अधिक से अधिक हो सके और कम से कम लोगों की हानि हो सके।

Scanned with CamScanner